

सं. ए-45011/3/2022-प्रशा.।।।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, 22, मार्च, 2022

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को जनवरी, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधरी)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नं. 23095091

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. वित्त राज्य मंत्री के प्रधान सचिव, वित्त सचिव के पीपीएस, सचिव (आ.का.) के पीपीएस, सचिव (राजस्व) के पीपीएस, सचिव (व्यय) के पीपीएस, सचिव (दीपम) के पीपीएस।
11. श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, जेएस एंड एफए (वित्त)।
14. श्री ए.एम. बजाज, अपर सचिव (एफएम), आ.का.वि.
15. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव (बजट), आ.का.वि.।
16. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.
17. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
वरिष्ठ सलाहकार (सीएण्डसी/एफएसएलआर/एफएस और सीएस)/ संयुक्त सचिव (बीसी और आईईआर)/ संयुक्त सचिव (निवेश)/ सलाहकार (आईईआर) सीएए।
18. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम और सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
19. गार्ड फाइल - 2022

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

विषय: जनवरी, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश

I. इस माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. वृहदआर्थिक अवलोकन:

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम और पहला संशोधित अनुमान बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 में 6.6% की कमी के बाद 2021-22 में 9.2% की वास्तविक जीडीपी विस्तार देखने की उम्मीद है। इसका तात्पर्य यह है कि समग्र आर्थिक गतिविधि पूर्व-महामारी के स्तर से आगे निकल गई है।

सरकारी खर्च से महत्वपूर्ण योगदान के साथ 2021-22 में कुल खपत में 7.0% की वृद्धि होने का अनुमान है। इसी तरह, अवसंरचना पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण सकल स्थायी पूंजी निर्माण महामारी पूर्व स्तर से अधिक हो गया। 2021-22 में अब तक वस्तुओं और सेवाओं दोनों का निर्यात असाधारण रूप से मजबूत रहा है, लेकिन घरेलू मांग में सुधार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में सुधार के साथ आयात में भी मजबूती आई है।

महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं और पिछले वर्ष 3.3% बढ़ने के बाद 2021-22 में इस क्षेत्र के 3.9% बढ़ने की उम्मीद है। पहले अग्रिम अनुमान और पहले संशोधित अनुमान बताते हैं कि उद्योग के जीवीए (खनन और निर्माण सहित) में 2020-21 में 3.3% के अनुबंध के बाद 2021-22 में 11.8% की

वृद्धि होगी। सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से ऐसे खंड जिनमें मानव संपर्क शामिल है। पिछले साल के 7.8 फीसदी के संकुचन के बाद इस वित्त वर्ष में इस क्षेत्र के 8.2% बढ़ने का अनुमान है।

प्रमुख बहु-पक्षीय और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को उम्मीद है कि भारत 2021 (वित्त वर्ष 21-22) में 8%-10% के बीच वृद्धि करेगा और ऐसा ही सरकार भी करती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.0-8.5% की जीडीपी वृद्धि देखी जा सकती है। आईएमएफ ने 2021-22 और 2022-23 दोनों में भारत की वास्तविक जीडीपी 9% और 2023-24 में 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह भारत को तीनों वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करता है। श्रम ब्यूरो ने अर्थव्यवस्था के नौ प्रमुख क्षेत्रों (अर्थात् विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवा गतिविधियां) के लिए 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में दूसरे तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) के आंकड़े जारी किए हैं। क्यूईएस के दूसरे दौर (जुलाई-सितंबर, 2021) से नौ चयनित क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार लगभग 3.10 करोड़ निकला, जो क्यूईएस (अप्रैल-जून, 2021) के पहले चक्र से अनुमानित रोजगार (3.08 करोड़) से 2 लाख (0.65%) अधिक है। । क्षेत्रवार विकास दर **अनुबंध** में दी गई है।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) अनुपूरक अनुदान मांग का दूसरा बैच संसद में पारित किया गया है।

(ii) भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के तहत निम्नलिखित ऋण सहायता (एलओसी) विस्तारित और समर्थित की गई:

(क) रक्षा परियोजनाओं के लिए मेडागास्कर सरकार को 100 मिलियन अमरीकी डालर का एलओसी; तथा

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए श्रीलंका सरकार को 500 मिलियन अमरीकी डालर का अल्पकालिक एलओसी।

(iii) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

(क) केएफडब्ल्यू के साथ सूरत मेट्रो परियोजना के लिए 2 मिलियन यूरो का अनुदान;

(ख) केएफडब्ल्यू के साथ स्थायी भूमि प्रबंधन मेघालय के लिए 4.49 मिलियन यूरो का अनुदान;

(ग) विश्व बैंक से पश्चिम बंगाल बिजली वितरण ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 135 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण;

(घ) विश्व बैंक से केरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए 105 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण; तथा

(ड) दो परियोजनाओं के लिए 605 मिलियन अमरीकी डालर के दो ऋण, रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया रेस्पॉन्सिव कोविड-19 वैक्सीन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से केरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट।

(iv) छह अन्य प्राधिकरणों/नियामकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के छह द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(v) निम्नलिखित के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं:

(क) कवि मुद्रना की 150 वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमों में संशोधन को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिसूचित किया गया है, जो बोर्ड को और अधिक शक्तियां प्रदान करता है;

(ग) सेबी (वॉल्ट प्रबंधक) विनियमन, 2021;

(vi) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) अधिनियम, 2019 के तहत निम्नलिखित नियम जारी किए गए हैं:

(क) बीमा व्यापार विनियम, 2021 का पंजीकरण;

(ख) बीमा मध्यस्थ विनियम, 2021; तथा

(ग) जहाज या समुद्री पोत, जहाज या समुद्री पोत के इंजन के संचालन और वित्तीय पट्टे के संचालन और वित्तीय पट्टे को शामिल करने के लिए 'जहाज पट्टे' के विनिर्देश के संबंध में विनियमन।

(vii) अवसंरचना क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(क) एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग -पीपीपी स्वामित्व, जीवन चक्र, जोखिम, वित्तीय रणनीतियों, संपूर्ण पीपीपी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(ख) विदेशी, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय, यूनाइटेड किंगडम-ज्ञान विनिमय कार्यक्रम-अवसंरचना परियोजना प्राधिकरण (यूके पीपीपी एक्सपीरियंस) का अनुभव साझा करना, बुनियादी विकास के लिए यूके का दृष्टिकोण, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत परियोजना प्राथमिकता।

(viii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) में संशोधन को केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीजसी) की शुरुआत के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान करने के लिए वित्त विधेयक 2022 में शामिल किया गया था।

(ix) मंत्रिमंडल ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) को 31 मार्च 2026 तक, या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो और 9,966 करोड़ रुपये की राशि के लिए, जैसा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुशंसित है, के सुधार और निरंतरता को मंजूरी दी।

(x) माह के दौरान निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:

(क) बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तपोषण की मांग करने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति की 124वीं बैठक;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मध्य-वर्ष की संचालन समिति की बैठक - दक्षिण एशिया क्षेत्रीय तकनीकी और प्रशिक्षण केंद्र (एसएआरटीटीएसी);

(ग) प्रारंभिक चेतावनी समूह (ईडब्ल्यूजी) की 27वीं बैठक; वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों और निगरानी के साथ-साथ जोखिम दृष्टिकोण पर असर डालने वाले प्रमुख आर्थिक विकास पर चर्चा करना;

- (घ) भारत और सिंगापुर के बीच आपसी व्यापार में तेजी लाने के लिए कार्य समूह की पहली आभासी बैठक;
- (ङ) आर्थिक कल्याण पर अधिकार प्राप्त समूह की बैठक;
- (च) सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) वार्ता का तीसरा दौर;
- (छ) उज्बेकिस्तान के साथ बीआईटी पर पांचवें, छठे और सातवें दौर की बातचीत; पाठ सातवें दौर में संपन्न हुआ।
- (ज) यूनाइटेड किंगडम के साथ बीआईटी/निवेश संधि/विदेश व्यापार समझौते (एफटीए) के निवेश अध्याय के लिए पहले दौर की बातचीत;
- (झ) विभिन्न नीति समीक्षा और निवेश कार्यों पर विचार करने के लिए एआईआईबी निदेशक मंडल की बैठक; बोर्ड ने (क) वसूली परियोजना के लिए भारत उत्तरदायी कोविड-19 टीके और (ख) पश्चिम बंगाल बिजली वितरण ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी के निर्देशों/आदेशों का पालन न करना

शून्य

5. माह के दौरान स्वीकृत एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या : 01

विभाग में स्वीकृति का इंतजार : 11

तालिका 1: सकल घरेलू उत्पाद और उसके घटकों के मांग पक्ष में वार्षिक वास्तविक वृद्धि (प्रतिशत)				
क्षेत्र	2019-20 (दूसरा सं.अनु.)	2020-21 (पहला सं.अनु.)	2021-22 (पहला अग्रि. अनु.)	2019-20 में वसूली
कुल खपत	4.9	-4.5	7.0	100.5
सरकारी खपत	3.4	3.6	7.6	115.0
निजी खपत	5.2	-6.0	6.9	97.8
कुल निश्चित पूंजी निर्माण	1.6	-10.4	15.0	105.2
निर्यात	-3.4	-9.2	16.5	111.6
आयात	-0.8	-13.8	29.4	111.6
सकल घरेलू उत्पाद	3.7	-6.6	9.2	101.6
स्रोत: एनएसओ				
टिप्पणी: सं.अनु. - संशोधित अनुमान, अग्रि. अनु. - अग्रिम अनुमान				

तालिका 2: स्थिर कीमतों (2011-12) पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)				
क्षेत्र	2019-20 (दूसरा सं.अनु.)	2020-21 (पहला सं.अनु.)	2020-21 (पहला अग्रि. अनु.)	2019-20 में वसूली
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	5.5	3.3	3.9	106.9
उद्योग	-1.4	-3.3	11.8	104.2
खनन और उत्खनन	-1.5	-8.6	14.3	104.7
उत्पादन	-2.9	-0.6	12.5	104.8
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	2.2	-3.6	8.5	110.5
निर्माण	1.2	-7.3	10.7	100.8
सेवाएं	6.3	-7.8	8.2	100.0
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	5.9	-20.2	11.9	91.8
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं	6.7	2.2	4.0	103.1
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	6.3	-5.5	10.7	107.5
मूल कीमत पर जीवीए	3.8	-4.8	8.6	102.3
स्रोत: एनएसओ				
टिप्पणी: सं.अनु. - संशोधित अनुमान, अग्रि. अनु. - अग्रिम अनुमान				

मुद्रास्फीति- सीपीआई-सी, डब्ल्यूपीआई (प्रतिशत में)			
	दिसंबर -20	नवंबर -21	दिसंबर -21
सीपीआई-सी	4.59	4.91	5.59
डब्ल्यूपीआई	1.95	14.23	13.56

स्रोत: सीपीआई-सी और ओईए के लिए एनएसओ, डब्ल्यूपीआई के लिए डीपीआईआईटी

टिप्पणी: पिछले दो महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति और पिछले एक महीने के लिए सीपीआई-सी मुद्रास्फीति अस्थायी है।

मौद्रिक विकास	
मद	21.1.2022
पॉलिसी रेपो रेट	4.0
10-वर्ष जी-सेक सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल)	6.63
बैंक ऋण वर्ष वर्ष वृद्धि-दर-#	8.0

अनंतिम।

तालिका 5: पण्य व्यापार निष्पादन (सीमा शुल्क के आधार पर) (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)			
	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
दिसंबर 2020	27.2	42.9	(-) 15.7
दिसंबर 2021	37.8	59.5	(-) 21.7

तालिका 6: सेवा व्यापार प्रदर्शन (अरब अमेरिकी डॉलर में)			
नवम्बर 2021	20.1	12.6	7.5
स्रोत: वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की दिनांक 13.1.2022 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अनंतिम डेटा।			

तालिका 7: भुगतान संतुलन		
मद	2020-21 (अप्रैल-सितंबर)	2021-22 (अप्रैल-सितंबर) (प)
चालू खाता शेष (अरब अमेरिकी डॉलर में)	34.4	(-) 3.0
चालू खाता शेष/जीडीपी (प्रतिशत)	3.0	(-) 0.2
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक		

तालिका 8: विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	
अंत-मार्च, 2021	577.0
21.1.2022	634.3
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक	

तालिका 9: भारतीय रुपये की विनिमय दर (विदेशी मुद्रा रुपये प्रति यूनिट)				
	अमेरिकी डॉलर	पाउंड स्टर्लिंग	यूरो	जापानी येन
24.1.2022	74.5788	100.9886	84.4093	65.5200
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक /fbll.org.in				

तालिका 10: विदेशी ऋण (बिलियन अमेरिकी डॉलर)			
	सितंबर 2020 के अंत में के रूप में पीआर (1)	सितंबर 2021 के अंत में के रूप में पी (2)	प्रतिशत भिन्नता $[(2/1)-1]*100$
कुल विदेशी बकाया ऋण	556.8	593.1	6.5
स्रोत: सितंबर 2021 के अंत तक विदेशी ऋण पर तिमाही रिपोर्ट, आर्थिक कार्य विभाग			

तालिका 11: औद्योगिक उत्पादन विशेषताएं मासिक वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) प्रतिशत में			
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	सितंबर 2020	अक्टूबर 2020	नवंबर 2020
	1	4.5	1.6
सूचकांक	सितंबर 2021	अक्टूबर 2021	नवंबर 2021
	3.3	4	1.4

कक्षा 12: आठ प्रमुख उद्यम समर्थन वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) प्रतिशत में			
	अक्टूबर 2020	नवंबर 2020	दिसंबर 2020
आठ प्रमुख उद्योग (आईसीआई)	(-) 0.5	(-) 1.1	0.4
	अक्टूबर 2020	नवंबर 2021	दिसंबर 2021
	8.4	3.4	3.8
